



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 503]  
No. 503]

नई विल्सी, रविवार, नवम्बर 12, 1978/कार्तिक 21, 1900  
NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 12, 1978/KARTIKA 21, 1900

इस भाग में विशेष पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### पृष्ठ संख्या

प्रधिकार सूचना

नई विल्सी, 12 नवम्बर, 1978

कांग्रेस 645(म).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्न-  
लिखित भारत सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता  
है:—

प्रादेश

यह: मूल, नीलम संजीव रेण्डी, भारत के राष्ट्रपति को, पाइडेंसी संघ  
राज्य और भौतिक संघासन के लिए रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट पर  
विवार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति  
बहुत ही गई है जिसमें पाइडेंसी संघ राज्य और भौतिक संघासन, संघ राज्य  
को विभाजित करना अविविधिम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं घलाया  
जा सकता;।

यह: अब, अधिनियम की द्वारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस  
निम्न दूसरे संघर्ष वरने वाली अभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए,  
मैं इस घोषणा द्वारा—

(क) अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों का प्रबंधन, उक्त पाइडेंसी  
संघ राज्य और भौतिक संघ में इस प्रादेश की तारीख से छह  
मास की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ, अर्थात्:—  
द्वारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का  
खण्ड (क); द्वारा 7 में, उपधारा (1), (3) और (4),  
उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ग) और उस उपधारा

का प्रथम परन्तुक; और उपधारा (5) का उत्तमा भाग  
जो उपाध्यक्ष के बेतन और भत्तों से संबंधित है;

द्वारा 8 से 12 (जिनमें दोनों द्वारा सम्मिलित हैं)  
द्वारा, 15 से 17 (जिनमें दोनों द्वारा सम्मिलित हैं), और  
द्वारा 22;

द्वारा 27 की उपधारा (1) का उत्तमा भाग जिसके  
लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है और  
उसी द्वारा की उपधारा (3) के खण्ड (ग) का उत्तमा भाग  
जो उपाध्यक्ष के बेतन और भत्तों से संबंधित है;

द्वारा 30 की उपधारा (1) का उत्तमा भाग जिसके  
लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है;

द्वारा 33, द्वारा 34 की उपधारा (2) और द्वारा  
36;

द्वारा 44 और 45;

द्वारा 46 की, उपधारा (1) और उपधारा (2) में,  
निम्नलिखित उपबंध, अवैध:

“क्या अपने मंत्रियों की दस्तावेज पर या अन्यथा  
विभाग द्वारा”; और

द्वारा 50 का उत्तमा भाग जो मंत्रिमंडल से संबंधित है;  
प्रौढ़

(ब) निम्नलिखित भारतीय और पारिषदामिक उपबंध व्यापार हैं  
जो मूल पूर्वोक्त अवधि के द्वारा निवापात के अनुच्छेद 220

के अनुसार पांचवें संघ राज्य धोत्र का प्रशासन करने के लिए आवश्यक और समीक्षीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्:—

- (1) उक्त संघ राज्य धोत्र की विधान सभा भग की जाती है;
- (2) अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री उस हैसिपत से अपने पद पर नहीं रहेंगे;
- (3) जब तक संवर्भ से अन्यथा अवैधित न हो, उक्त संघ राज्यधोत्र के संबंध में, अधिनियम की धारा 6, 23, 27, 28, 30 और 49 में प्रशासक के प्रति किसी निर्देश का अर्थ राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा और धारा 23, 27 से 31 (जिनमें दोनों धारा सम्मिलित है) 48 और 49 में किसी संघ राज्यधोत्र की विधानसभा के प्रति किसी शब्दों में निर्देश का जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों का और शक्तियों से है, अर्थ, संसद के प्रति निर्देश लगाया जाएगा।

हस्ता ०/-  
नीलम संजीव रेडी  
भारत का राष्ट्रपति

नई दिल्ली,

12 नवम्बर, 1978

[सं. ००-११०१२/९/७८-यू.०८८०]  
म. ०. कम्पानी, घण्टर सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 1978

**S.O. 645 (E).**—The following Order made by the President is published for general information:—

#### ORDER

Whereas I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, have received a report from the Administrator of the Union territory of Pondicherry and after considering the report, I am satisfied that a situation has arisen in which the administration of the Union territory of Pondicherry cannot be carried on in accordance with the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), (hereinafter referred to as "the Act");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby—

(a) suspend, for a period of six months from the date of this order, in relation to the said Union territory of

Pondicherry, the operation of the following provision of the Act, namely:—

sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 6;

in section 7, sub-sections (1), (3) and (4), clauses (b) and (c) of sub-section (2) and the first proviso to that sub-section, and so much of sub-section (5) as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

sections 8 to 12 (both inclusive), sections 15 to 17 (both inclusive);

section 22;

so much of sub-section (1) of section 27 as requires the previous approval of the President and so much of clause (c) of sub-section (3) of the same section as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker;

so much of sub-section (1) of section 30 as requires the previous approval of the President;

section 33, sub-section (2) of section 34 and section 36; sections 44 and 45;

sub-section (1), and the following provision, namely, "whether taken on the advice of his Ministers or otherwise" in sub-section (2), of section 46; and

so much of section 50 as relates to the Council of Ministers; and

(b) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary and expedient for administering the Union territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period, namely:—

(i) the Legislative Assembly of the said Union territory is hereby dissolved;

(ii) the Chief Minister and the other Ministers appointed under sub-section (1) of section 45 of the Act shall cease to hold office as such;

(iii) in relation to the said Union territory, unless the context otherwise requires, any reference in sections 6, 23, 27, 28, 30 and 49 of the Act to the Administrator shall be construed as a reference to the President and any reference in sections 23, 27 to 31 (both inclusive), 48 and 49 to the Legislative Assembly of a Union territory by whatever form of words shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed as a reference to Parliament.

Sd/-

NEELAM SANJIVA REDDY, President of India  
New Delhi,  
the 12th November 1978.

[No. U-11012/9/78-UTL]  
M. L. KAMPANI, Addl. Secy.